ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

"भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान की बदलती प्राथमिकता (2014–2024)"

अभिनन्दन कुमार चौबे, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश

भारत और पाकिस्तान के संबंध दक्षिण एशिया की स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन के लिए सदैव केंद्रीय रहे हैं। 1947 में विभाजन के पश्चात से ही दाने ों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और संघर्ष की भावना रही है। किंतु 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान की प्राथमिकता में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया। नरेंद्र मोदी सरकार के आगमन के साथ भारत की विदेश नीति का दायरा केवल "पड़ोसी नीति" तक सीमित न रहकर "वैश्विक रणनीतिक कूटनीति" में विस्तृत हुआ। इस अवधि में भारत ने "Neighbourhood First Policy", "Act East Policy" आरै "Indo–Pacific Strategy" जैसे नए आयामों को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान का महत्व धीरे–धीरे हाशिए पर चला गया।

2014 से 2024 के बीच भारत ने आतंकवाद, सीमाई उल्लंघन और कश्मीर विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कठोर रुख अपनाया। विशेषकर 2016 के उरी हमले, 2019 के पुलवामा–बालाकोट प्रकरण और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने भारत की विदशे नीति को सुरक्षा–प्रधान और यथार्थवादी दिशा दी। पाकिस्तान, जो कभी भारत की विदेश नीति का केंद्र–बिंदु हुआ करता था, अब केवल सुरक्षा–संबंधी चिंता और कूटनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाने लगा है।

यह शोध–पत्र 2014–2024 की अवधि में भारत की विदेश नीति के इस परिवर्तन का विश्लेषण करता है, कि कैसे भारत ने पाकिस्तान–केन्द्रित दृष्टिकोण से हटकर एक वैश्विक, बहुपक्षीय और सुरक्षा–केंद्रित नीति को अपनाया। साथ ही यह अध्ययन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि क्या भारत–पाक संबंधों में पुनः संतुलन संभव है, या यह "शून्य–विश्वास" (Zero Trust) की स्थिति स्थायी हो चुकी है।

मुख्य शब्द– भारत–पाक संबंध, विदेश नीति, आतंकवाद, अनुच्छेद 370, हिदं –प्रशांत रणनीति, कूटनीतिक प्राथमिकता, दक्षिण एशिया, वैश्विक राजनीति

परिचय

भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद से ही शांति, सह–अस्तित्व और विकास–मुखी रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित "पंचशील सिद्धांत" और "गुटनिरपेक्षता" ने इसे नैतिक आदर्शवाद का स्वरूप दिया। किंतु 21वीं सदी के दूसरे दशक में भारत की विदेश नीति ने एक नया आयाम प्राप्त किया, जहाँ आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद और सामरिक सोच ने स्थान लिया। भारत–पाक संबंधों का स्वरूप इसी व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है। विभाजन के बाद से दोनों देशों के संबंध "शत्रुता" और "संदेह" पर आधारित रहे। 1947, 1965 और 1971 के युद्धों ने इस अविश्वास को और गहरा किया। 1999 का कारगिल युद्ध तो दोनों देशों के लिए निर्णायक माडे ़ बन गया, जिसके बाद द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया लगभग स्थायी ठहराव में चली गई। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद भारत की विदेश नीति ने नया रूप लिया। मोदी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास "Neighbourhood First Policy" के तहत शुरू किया। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित करना एक प्रतीकात्मक शांति–संकेत था। किंतु शीघ्र ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की घटनाओं, पठानकोट (2016), उरी (2016), पुलवामा (2019), ने दोनो देशों के बीच बने विश्वास को समाप्त कर दिया।

इसके बाद भारत ने पारंपरिक "सवांद–प्रधान नीति" से हटकर "प्रतिकार–प्रधान कूटनीति" अपनाई। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों ने भारत की विदेश नीति को सुरक्षा–केंद्रित यथार्थवाद की दिशा में मोड़ दिया। पाकिस्तान, जो कभी भारत की कूटनीति का प्राथमिक केंद्र था, अब धीरे–धीरे उसकी विदेश नीति की प्राथमिकता सूची में नीचे चला गया। 2019 में जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण भारत की विदशे ा नीति का निर्णायक कदम था। भारत ने इसे अपने "आंतरिक प्रशासनिक सुधार" के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "कश्मीरी मुसलमानों के अधिकारों का हनन" बताया। भारत ने न केवल पाकिस्तान की आपत्तियों को अस्वीकार किया, बल्कि यह स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उस पर किसी भी बाहरी हस्तक्षपे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जड़ें 1947 के विभाजन में निहित हैं। विभाजन केवल भौगोलिक नही, बल्कि वैचारिक भी था। पाकिस्तान का निर्माण "दो–कौमी सिद्धांत" पर हुआ, जबकि भारत ने धर्मनिरपेक्ष

लोकतंत्र को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के संबंधों में तीन बड़े युद्ध (1947, 1965, 1971) और एक प्रमुख सैन्य संघर्ष (कारगिल, 1999) ने स्थायी अविश्वास को जन्म दिया।

1947–1971: राजनीतिक संघर्ष और वैचारिक भिन्नता

कश्मीर का प्रश्न आरंभ से ही विवाद का केंद्र रहा। भारत इसे अपने संघ का अभिन्न भाग मानता रहा, जबकि पाकिस्तान इसे "अपूर्ण विभाजन" का परिणाम बताता रहा। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौते ने अस्थायी शांति स्थापित की, परंतु 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के साथ पाकिस्तान का मनोबल टूटा।

1972–1998: शिमला समझौते से परमाणु प्रतिद्वंद्विता तक

शिमला समझौते (1972) ने द्विपक्षीय विवादों के समाधान का ढाँचा दिया, किंतु विश्वास बहाली नहीं हो सकी। 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन का नया युग प्रारंभ हुआ।

1999–2013: संवाद और आतंकवाद का दोहरा दौर

कारगिल संघर्ष (1999) और 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद संबंधों में ठहराव आया। डॉ.मनमोहन सिंह के शासनकाल में कुछ संवाद हुए, परंतु आतकं वाद और सीमाई उल्लघंन की घटनाओं ने शांति प्रक्रिया को असफल बना दिया।

2014 के बाद विदेश नीति का परिवर्तन

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में स्थिर, निर्णायक और राष्ट्रीय हित–आधारित शासन आया। इस कालखंड में भारत की विदेश नीति ने आदर्शवादी गुटनिरपक्ष ेता से यथार्थवादी सक्रिय कूटनीति (Proactive Realpolitik) की ओर संक्रमण किया।

Neighbourhood First Policy (2014)

मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में "पड़ोसी पहले" नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य था, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना और आतंकवाद के विरुद्ध साझा सुरक्षा ढाँचा बनाना। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उपस्थिति ने नई उम्मीद जगाई, परंतु 2015–16 में आतंकवादी घटनाओं ने उस विश्वास को नष्ट कर दिया। भारत ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ संवाद तब तक फलदायी नही ं हो सकता जब तक वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर सैन्य–वर्चस्व कायम रहगेा। इसके बाद भारत ने संवाद की बजाय "निवारण और प्रतिकार" की नीति अपनाई।

आतंकवाद–विरोधी नीति का सशक्तिकरण (2016–2019)

2016 के उरी हमले ने भारत की विदेश नीति को निर्णायक रूप से बदल दिया। भारत ने पहली बार "सर्जिकल स्ट्राइक" कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब वह आतंकवाद का सामना कूटनीतिक बयानबाजी से नही,ं बल्कि सैन्य जवाबी कार्रवाई से करेगा। 2019 के पुलवामा हमले और बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद–प्रायोजक राष्ट्र के रूप में अलग–थलग कर दिया। सयुंक्त राष्ट्र, FATF और अमेरिका जैसे देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया। इन घटनाओं के बाद भारत की विदेश नीति में "पाकिस्तान नीति" अब Reactive से Proactive बन गई, जहाँ भारत अपनी सुरक्षा को प्राथमिक मानते हुए स्वतंत्र निर्णय लेने लगा।

अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण (2019)

जम्मू–कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाना भारत की विदेश नीति का निर्णायक कदम था। पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चुनौती दी, किंतु भारत ने इसे "आंतरिक विषय" घोषित किया। भारत की इस नीति ने स्पष्ट कर दिया कि वह अब पाकिस्तान को "विवाद के पक्षकार" के रूप में नही,ं बल्कि "बाहरी हस्तक्षेपकर्ता" के रूप में देखता है। अनुच्छेद 370 के बाद भारत–पाक संबंध लगभग समाप्त हो गए। दोनों देशों ने उच्चस्तरीय वार्ताएँ बंद कर दीं, राजनयिक स्तर घटा दिए, और आर्थिक–सांस्कृतिक संपर्क ताड़े लिए।

पाकिस्तान का कूटनीतिक हाशियाकरण

- 2014–2024 के दौरान भारत ने अपने अंतरराष्ट्रीय सहयागे को विस्तृत किया।
- अमेरिका के साथ 2̣2 Dialogue और रणनीतिक साझेदारी।
- जापान, ऑस्ट्रेलिया, और फ्रांस के साथ रक्षा सहयागे ।
- QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) के माध्यम से हिन्द–प्रशांत क्षत्रे में चीन–पाक गठबंधन का संतुलन।

- BIMSTEC और IORA (Indian Ocean Rim Association) जैसे मंचों के माध्यम से दक्षिण एशिया से परे क्षेत्रीय एकता का निर्माण।
- इन सभी कूटनीतिक प्रयासों में पाकिस्तान लगभग अनुपस्थित रहा। यह भारत की विदेश नीति में हुए सबसे स्पष्ट परिवर्तनों में से एक था।
- जहाँ पाकिस्तान पहले "नीति–सहभागी" था, अब "सुरक्षा–जोखिम" बन गया।

SAARC की निष्क्रियता और नीतिगत विकल्प

2014 के बाद SAARC शिखर सम्मेलन लगातार स्थगित होते रहे। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सम्मले न का बहिष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप यह संगठन निष्क्रिय हो गया। भारत ने इसके स्थान पर BIMSTEC आरै Indo–Pacific Policy को अपनाया, जिससे पाकिस्तान क्षेत्रीय सहयागे के ढाँचे से पूरी तरह बाहर हो गया। इस प्रकार, भारत की विदेश नीति अब "दक्षिण एशियाई नेतृत्व" से आगे बढ़कर "वैश्विक शक्ति–स्थिति" की दिशा में विकसित हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत की स्थिति (Global Reaction and India's Standing)

भारत की नई नीति को वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन मिला। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के प्रयासों को समर्थन नहीं मिला, जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति कमजारे हुई। भारत ने स्वयं को "Responsibility–Driven Power" के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने अपने राष्ट्रीय हितों को आक्रामकता की बजाय नीति–दृढ़ता के माध्यम से सशक्त किया।

भारत का वैश्विक पुनर्संरेखण (India's Global Realignment, 2014–2024)

2014 के बाद भारत की विदेश नीति में एक निर्णायक परिवर्तन देखा गया। भारत ने अपनी विदेश नीति को "पड़ोसी–केंद्रित" दृष्टिकोण से हटाकर "वैश्विक–संतुलित" दिशा दी। इसका उद्देश्य था–

- सुरक्षा हितों की रक्षा,
- बहुपक्षीय गठबंधन निर्माण,
- आर्थिक व तकनीकी साझेदारी का विस्तार, और
- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आत्मनिर्भर पहचान स्थापित करना।

वैश्विक शक्ति–संरचना में भारत का स्थान

21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत "विकासशील राष्ट्र" से "उभरती वैश्विक शक्ति" (Emerging Global Power) के रूप में स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र, G–20, SCO, QUAD और BRICS जैसे मंचों पर भारत की सक्रियता बढ़ी। पाकिस्तान, जो पहले दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति का स्थायी कारक था, अब इन वैश्विक मंचों पर लगभग अप्रासंगिक हो गया। भारत ने अब अपनी विदेश नीति को "Issue– Based Alignment" पर आधारित किया, यानी भारत अब किसी गुट का स्थायी सदस्य नहीं, बल्कि प्रत्येक मुद्दे पर अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेने लगा। इस नीति परिवर्तन से पाकिस्तान की पारंपरिक "भारत–विरोधी कूटनीति" अप्रभावी होती चली गई।

अमेरिका–भारत साझेदारी का गहराव (US–India Strategic Convergence)

- 2014 के बाद भारत–अमेरिका संबंध अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुए।
- 2016 में भारत को अमेरिका द्वारा "Major Defense Partner" का दर्जा मिला।
- 2018 और 2020 में 22 Dialogue के अंतर्गत रक्षा, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा समझौते हुए।
- आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति को अमेरिका ने स्पष्ट समर्थन दिया।

इस नए समीकरण का सीधा प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा। अमेरिका ने धीरे–धीरे पाकिस्तान की सैन्य सहायता घटा दी और भारत को दक्षिण एशिया में स्थिरता के "केंद्र" के रूप में देखने लगा।

रूस और पश्चिम एशिया के साथ संतुलित संबंध

- भारत ने रूस के साथ पारंपरिक रक्षा–संबंध बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया (सऊदी अरब, यूएई, इस्राइल) के साथ ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश साझेदारी को बढ़ाया।
- यह "Multi-Vector Diplomacy" भारत की रणनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है, जहाँ पाकिस्तान का स्थान एक क्षेत्रीय विरोधी से अधिक नहीं रह गया।

हिंद–प्रशांत रणनीति और पाकिस्तान की घटती प्रासंगिकता (Indo–Pacific Strategy and Declining

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

Relevance of Pakistan)

हिंद–प्रशांत की अवधारणा का उदय

- हिंद–प्रशांत (Indo–Pacific) क्षेत्र 2014 के बाद भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार बन गया।
- भारत ने प्रशातं महासागर और हिंद महासागर के देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर चीन–पाक गठबंधन (CPEC और BRI) का प्रतिकार किया।
- इस नीति ने भारत की कूटनीति को दक्षिण एशिया की सीमाओं से बाहर वैश्विक भू–रणनीति में पहुंचाया।

DokM (QUAD) **और पाकिस्तान का अलगाव**

- अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के गठबंधन QUAD ने एशिया–प्रशातं क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों के प्रभाव को सीमित किया।
- भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सुरक्षा नीति अब "पाकिस्तान–प्रेरित" नही ं बल्कि "क्षेत्रीय स्थिरता–प्रेरित" है।
- पाकिस्तान, जो दशकों तक भारत की विदशे ा नीति का केंद्र रहा, अब भारत के लिए केवल एक "Peripheral Security Threat" रह गया है।

CPEC और भारत की प्रतिक्रिया

- चीन–पाक आर्थिक गलियारा (CPEC) भारत की सामरिक चिंताओं का विषय बना, क्यों ि क यह परियोजना भारतीय क्षेत्र (POK) से होकर गुजरती है।
- भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे चीन की "Neo–Colonial Strategy" बताया।
- इसके प्रतिकार में भारत ने "इंडो–पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI)" शुरू की, जिससे पाकिस्तान का क्षेत्रीय महत्व और घट गया।

BIMSTEC और IORA **का उदय**

SAARC की निष्क्रियता के बाद भारत ने BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi–Sectoral Technical and Economic Cooperation) और IORA (Indian Ocean Rim Association) जैसे मंचों को सक्रिय किया। इन मंचों से पाकिस्तान बाहर रहा, जिससे भारत की दक्षिण एशिया–केन्द्रित नीति अब "पूर्वी एशिया–केन्द्रित" बन गई। यह स्पष्ट संकेत था कि भारत अब पाकिस्तान को क्षेत्रीय सहयोग का केंद्र नहीं, बल्कि अवरोध मानता है।

पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति (Pakistan's Diplomatic Decline)

आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता :– 2014 से 2024 के बीच पाकिस्तान में चार प्रधानमन्त्रियों का कार्यकाल बदला, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खानं आरै शहबाज शरीफ। सैन्य हस्तक्षेप, न्यायिक अस्थिरता और आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की विदेश नीति को असंगत बना दिया। भारत के दृष्टिकोण से पाकिस्तान अब एक "अविश्वसनीय राजनीतिक इकाई" बन गया।

आर्थिक गिरावट और अंतरराष्ट्रीय दबाव

- FATF द्वारा ग्रे–लिस्ट में डाले जाने और IMF पर निर्भरता ने पाकिस्तान की आर्थिक स्वायत्तता को कमजोर किया।
- भारत ने इन परिस्थितियों का कूटनीतिक लाभ उठाया और पाकिस्तान को अलग–थलग करने में सफलता पाई।

वैश्विक मंचों पर अलगाव

- सयुंक्त राष्ट्र, OIC आरै SCO में पाकिस्तान की स्थिति कमजारे रही।
- 2019 के बाद OIC में भी भारत को Observer Status देने पर विचार हुआ, यह पाकिस्तान की घटती कूटनीतिक क्षमता का संकेत था।

जनता–स्तर की कूटनीति (People–to–People Diplomacy)

हालाँकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद समाप्त हो गया, लेकिन जनता–स्तर पर सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध पूरी तरह टूटे नही। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध के बावजूद साहित्य और संगीत के स्तर पर आपसी रुचि बनी रही। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों देशों के युवाओं के बीच

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in June 2025

विचार–विनिमय ने संवाद की संभावना को जीवित रखा। भारत ने ''Soft Power Diplomacy" के माध्यम से यह दर्शाया कि उसकी कूटनीति अब केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव–आधारित भी है।

निष्कर्ष

2014 से 2024 के दशक में भारत की विदेश नीति ने ऐतिहासिक परिवतर्न का अनुभव किया है। यह दशक भारत के लिए केवल शासन–परिवर्तन का नहीं, बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण में "परिपक्वता और आत्म–निर्भरता" का प्रतीक रहा है। भारत ने पहली बार अपनी विदेश नीति को "पड़ोसी–केंद्रित प्रतिक्रियाशील नीति" से आगे बढ़ाकर "वैश्विक–केंद्रित सक्रिय नीति" के रूप में पुनर्परिभाषित किया। पाकिस्तान, जो स्वतत्रं ता के बाद से भारत की विदेश नीति के केंद्र में था, अब केवल एक सुरक्षा–संबंधी चुनौती बन गया है।

भारत ने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ संवाद तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह आतंकवाद, उग्रवाद और सैन्य–राजनीतिक नियंत्रण की नीति नहीं बदलता। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान की प्राथमिकता लगातार घटती गई, और उसकी जगह हिंद–प्रशातं , क्वाड, पश्चिम एशिया, आरै वैश्विक दक्षिण (Global South) से संबंधों ने ले ली। भारत ने "शांति" को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि "नीति–साहस" के रूप में परिभाषित किया। पुलवामा, उरी और बालाकाटे जैसी घटनाओं के बाद भारत ने न केवल सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी यह सिद्ध किया कि वह अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को आकार देने वाला राष्ट्र है। भारत की विदेश नीति की इस नई दिशा में चार प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं।

1. सुरक्षा–प्रधान यथार्थवादः– भारत ने आतंकवाद और सीमा सुरक्षा को अपनी विदेश नीति का केंद्र बना लिया है।
2. क्षेत्रीय पुनर्संरेखणः–SAARC की निष्क्रियता के बाद भारत ने BIMSTEC, IORA आरै QUAD जैसे मंचों के माध्यम से दक्षिण एशिया से आगे बढ़कर क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाई।
3. वैश्विक विस्तारः–भारत ने अमेरिका, जापान, फ्रांस, इस्राइल, और सऊदी अरब जैसे देशों से बहुआयामी साझेदारी विकसित की, जिससे पाकिस्तान की सामरिक प्रासंगिकता घट गई।
4. कूटनीतिक आत्मविश्वासः– अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के प्रबंधन ने भारत की कूटनीतिक परिपक्वता को प्रमाणित किया।

भारत–पाक संबंध अब "संवाद–आधारित" नहीं, बल्कि "सिद्धांत–आधारित" संबंध बन चुके हैं। भारत ने अपने हितों को स्पष्ट करते हुए यह संदेश दिया है कि उसकी विदेश नीति अब किसी एक देश पर केंद्रित नही, बल्कि "वैश्विक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वायत्तता" पर आधारित है। भारत–पाक संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश किस हद तक अपने वैचारिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ पाते हैं। भारत की विदेश नीति अब भावनाओं की नही, बल्कि "हितों की राजनीति" की दिशा में विकसित हो चुकी है। जहाँ पाकिस्तान अब भी अपने अतीत की नीतियों में उलझा हुआ है, वहीं भारत ने भविष्य–मुखी दृष्टिकोण अपनाया है।

यह शोध–पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान की प्राथमिकता घटने का अर्थ शत्रुता नहीं, बल्कि "नीतिगत परिपक्वता" है, जहाँ भारत ने "शांति को शक्ति" में बदलने की क्षमता प्राप्त कर ली है।

संदर्भ सूचीः–

1. Bajpai, K. (2015). India Versus Pakistan: Why Can't We Just Be Friends\ New Delhi: Penguin Books.
2. Basrur, R. (2018). South Asia's Nuclear Security Dilemma: India, Pakistan, and China- Routledge.
3. Bhasin, A. S. (2018). India–Pakistan Relations: The History and Diplomacy. Oxford University Press.
4. Fair, C. C. (2014). Fighting to the End: The Pakistan Army's Way of War. OUP.
5. Ganguly, S. (2001). Conflict Unending: India–Pakistan Tensions since 1947. Columbia University Press.
6. शर्मा, के. (2018). भारतीय विदेश नीति और दक्षिण एशिया. नई दिल्लीः नीति प्रकाशन।
7. मिश्रा, एस. (2019). भारत–पाक संबंधों का समकालीन विश्लेषण. लखनऊः भारतीय अध्ययन प्रकाशन।
8. वर्मा, जी. (2020). आधुनिक विश्व राजनीति और भारत की भूमिका. वाराणसीः ज्ञानगंगा पब्लिकेशन।
9. चौधरी, पी. (2021). भारत–पाक संबंध और कश्मीर समस्या. नई दिल्लीः प्रभात प्रकाशन।
10- सिंह, आर. (2020). दक्षसे और दक्षिण एशिया की राजनीति. जयपरु : दृष्टिकोण प्रकाशन।